Status of implementation of recommendations contained in the Thirty-Fifth, Thirty-Sixth, Thirty-Seventh and Thirty-Eighth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of my colleague, Shri Ajay Bhatt, I lay the following statements regarding:—

(a) Status of implementation of recommendations contained in the 35th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-23 on 'General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 19 and 22);

(b) Status of implementation of recommendations contained in the 36th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-23 on 'Army, Navy, Air Force, Joint Staff, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik Schools (Demand Nos. 20 and 21);

(c) Status of implementation of recommendations contained in the 37th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2023-24 on 'Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21); and

(d) Status of implementation of recommendations contained in the 38th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2023-24 on 'Directorate of Ordinance (Coordination and Services) — New DPSUs, Defence Research and Development Organisation and National Cadet Corps (Demand Nos. 20 and 21)'.

REGARDING EXPUNGED REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, 2 फरवरी को मैंने यहां पर चंद प्वाइंट्स अपने भाषण में उठाए थे, उनको रिकॉर्ड्स से बाहर कर दिया गया है। इसी के संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहला जो मेरा रिमार्क expunge हुआ है...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं कारण बताता हूं।

श्री सभापति: नहीं, सर। If you will read what has been expunged, it will not be appropriate. So, you may please indicate the premise of it, I am open to it. Please. I have gone through your communication.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मेरे जो रिमार्क्स expunge हुए हैं, मैंने उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया, तो किसी भी rule of procedure का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा प्वाइंट यह है कि जो मेरे रिमार्क्स expunge हुए हैं, उनमें रूल्स के मुताबिक किसी भी 'persons in high authority' के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। Rule 238 (v) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha के explanation में 'persons in high authority' का मतलब साफ-साफ लिखा गया है। अगर आप इजाज़त दें, तो मैं वह भी पढ़ूंगा।

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: Rule 238A कहता है, "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any other Member or a Member of the House unless the Member making the allegation has given previous intimation to the Chairman and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply: Provided that the Chairman may at any time prohibit any Member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the Council or that no public interest is served by making such allegation." रूल 238(v), इसमें यह भी कहा गया है कि इस रूल के मुताबिक, 'reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms'. सर, यह रूल 238(v) के मुताबिक हो या रूल 238ए के मुताबिक हो, मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया।

दूसरा, मैंने 'persons in high authority' का मतलब आपके सामने रखा है कि इस डेफिनिशन में कोई भी मुख्य मंत्री किसी भी तरीके से कवर नहीं होता है, क्योंकि सदन में मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई भी सब्सटांटिव मोशन नहीं लाया गया।

श्री सभापति: आप एक बार Explanation to Rule 238 पढ़ दें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं, नहीं, पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप कह दीजिए कि यह इसके मुताबिक है।

मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि रूल्स के मुताबिक इसमें प्रायर नोटिस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि न तो जिनकी बात हो रही थी, वे इस हाउस के सदस्य हैं और जो मैंने बोला, वह बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड था। मैंने जिस ट्वीट का ज़िक्र किया, वह फैक्चुअली बिल्कुल सही है। बाद में स्पष्टीकरण जरूर आया, लेकिन मैंने जो भी बोला, वह फैक्ट्स के आधार पर बोला।

सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा मौका होता है, जब हमें कई विषयों पर व्यापक चर्चा करने का मौका मिलता है। मुझे लगा कि एक प्रदेश का मुख्य मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो यह मेरा कर्तव्य और हक है कि मैं इन मुद्दों को सदन में उठाऊँ। मैंने बोलते हुए न ही किसी मुख्य मंत्री का नाम लिया, न ही उस राज्य का नाम लिया। मैंने उसका ज़िक्र भी नहीं किया। इसलिए जो मेरे शब्दों को एक्सपंज किया गया, उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनःस्थापित किया जाए। आपने उन शब्दों को, पूरे दो पेज का भाषण काट दिया। मेरे दो पेज का भाषण काटने के बाद, उसका उद्देश्य अलग-अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आँकड़ा, आपने गड़बड़ किया। उसमें क्या हो गया ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आपने क्या कहा ...(**व्यवधान**)... आपने क्या कहा ...(**व्यवधान**)... गड़बड़ शुरू हो गई। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Have it from me...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: वह शब्द इस बार भी बोला, वह आगे था, लेकिन आपने गड़बड़ में उसके सामने व्यवधान लिख दिया।

MR. CHAIRMAN: When the Leader of the Opposition ...(*Interruptions*)... One minute. ...(*Interruptions*)... When the Leader of the Opposition is on his legs, I expect, you can appreciate but you cannot raise a disturbance. ...(*Interruptions*)... Please, nothing. ...(*Interruptions*)... Yes.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, इसमें क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ होता है। जब आप गड़बड़ करके स्टॉप कर देते हैं, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं ...

श्री सभापति: आपने बोला ही इस तरीके से था।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं, नहीं। वह आपकी है। आपके आगे मैं पढ़ूँ! आपके आगे था, पूरा गड़बड़ हुआ, हिन्दी में क्या बोलते हैं, व्यवधान, आपने उसके सामने लिखा, तो वह शब्द चला गया। मैं यह कह रहा हूँ कि इसके लिए पूरा, आप देखिए, 1.55 बजे मैंने * शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर दो ...

श्री सभापति: आप वह मत पढ़िए, मैंने एक्सपंज किया हुआ है। वह अनपार्लियामेंटरी था।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं, नहीं। मुझे एक्सपंज के बारे में ही कहना है, मेरा दूसरा नहीं है। मुझे एक्सपंज के बारे में कहना है। देखिए, 2 बजे onwards ...

MR. CHAIRMAN: The expunged portion may not be read. आपने * पढ़ा न। * has been held unparliamentary.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No. यह शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है, 'untouchability' है। Untouchability removal के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में कहा गया है।

श्री सभापति: खरगे जी, आज मैं शीशे में दो बार देख कर आया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मुझे ही देख कर बोलना है। इसलिए आप भी इधर ही देख कर बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, आपको देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि आप इतने सीनियर वकील हैं। अगर आप इधर देखें तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। सर, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम सत्य बात कहते हैं, तो आप उधर ज़रा ज्यादा ही देखते हैं। उस वक्त आपको इधर आकर्षित करने के लिए हमें कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है।

सर, 1.55 हुआ, 2.00 हो गया और 2 बजे onwards - उसमें भी आपने वह काट दिया। फिर 2.40 को आपने काट दिया। इसीलिए मेरा यह कहना है कि हम जो कहना चाहते हैं, अगर लोग उसको तोड़-मरोड़ कर पढ़ेंगे, तो क्या होगा - आपने जो चीजें बोली हैं, वे इसमें नहीं हैं। मेरे साथ ऐसा हर दफा हो रहा है। This is the second or third time that my speeches are cut. This is the letter which I have written to you. मैं बाहर प्रेस को बोलना नहीं चाहता था, unless, I can bring it to your notice. What is this, Sir? Every time, it is being done.

MR. CHAIRMAN: Now, listen to me.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में इतना बोला गया है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: You have made your point, please confine to the issue.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इतनी चर्चा हुई है और मैं जब बोलता हूँ, तो उसको निकाल देते हैं, what is this? इसीलिए कृपा करके आपने जो निकाला है, उस पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we have 'Unparliamentary Expressions', a book from Lok Sabha Secretariat which says * is unparliamentary. Secondly, hon. Members, I have received a written communication from hon. Leader of the Opposition, I have gone through it. I will give my ruling on it. But, I may indicate to the House that his communication is in two parts. He has listed four items in particular. Item No. 1 was related to a word which was expunged because it is unparliamentary. The other item Nos. 2, 3 and 4 were recorded after I had said, nothing will go on record. But, I will give my ruling. This matters because this is a platform where everyone has a free right of expression in accordance with the rules. I will give my ruling on this.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, तब तक तो मेरी पूरी फजीहत हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Sir, it was considered to be unparliamentary, but, now, there are Acts in place. The time has changed. When the time changes, the law has to change. ...*(Interruptions)*... Sir, I am presenting to you.

MR. CHAIRMAN: Dr. K. Keshava Rao, what do you want to say?

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, there have been Acts mentioning untouchability. It has been accepted legally as a terminology. It is for you, I want you to balance it. It is for the Chair or for the House to correct it in the book.

MR. CHAIRMAN: I will be too happy to revise Unparliamentary Expressions and I may constitute a committee on that point so that senior Members of the House as well as young Members, unless they take an offence at it... ...*(Interruptions)*... We will have it examined. To the extent what the Leader of the Opposition has said, I will give my ruling on that.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, मेरा एक प्वाइंट आफ ऑर्डर है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा।

MR. CHAIRMAN: Under which rule?

श्री प्रमोद तिवारी: सर, शब्दों का निकाला जाना - अगर आपको लगे कि कोई शब्द unparliamentary है, तो आप उसे निकाल देंगे, लिख देंगे और कहेंगे कि यह कार्यवाही में नहीं रहेगा। लेकिन सर, जिस तरह page by page, 10-10 मिनट की speeches निकाली जा रही हैं, राज्य सभा में ऐसा कभी नहीं होता था।

श्री सभापति: प्रमोद जी, प्लीज़।

श्री प्रमोद तिवारी: पार्लियामेंट में वह word निकाला जाता है, पूरा reference नहीं।

MR. CHAIRMAN: Pramodji, the Leader of the Opposition had very firmly, categorically put across his point. If you want my tentative response, you have the book; read Rule 238A proviso. What does the proviso say? "Provided the Chairman may at any time prohibit any Member from making any such allegation if he is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the Council.. " -- not some individual -- ".. or that no public interest is served by making such an allegation." ...*(Interruptions)*...We are not having a discussion on this. I have reserved my ruling. I will come with it. The House will have the benefit of it, I will have the benefit of it. We will now take up matters raised with permission of Chair. Shri Kartikeya Sharma.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: We will now take up matters raised with permission of Chair. Shri Kartikeya Sharma.

Concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills

SHRI KARTIKEYA SHARMA (HARYANA): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this important issue which is the concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. ...*(Interruptions)*...

There are umpteen saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body to the family due to outstanding bills.